International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 02(I), April - June, 2021, pp.151-157

आत्मनिर्भर भारतः राजस्थान के लघु उद्योगों के संदर्भ में

डॉ. हवा भंवर शेखावत*

सार

आत्मनिर्भर होना एक युवा के साथ साथ एक देश और राज्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब देश आत्मनिर्भर होगा तो वह हमेशा ही अपने विकास के रास्ते पर नये कदम लेता रहेगा और उसे किसी भी अन्य पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोविड–19 के कारण उपजी हुई परिस्थितियों के बाद देश के नागरिकों को सशक्तीकरण करने की आवश्यकता है ताकि वे देश से जूडी समस्याओं का समाधान कर सके तथा बेहतर भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकें। आत्मनिर्भर भारत के लिये आवश्यक है कि सर्वप्रथम राज्य आत्मनिर्भर बनें इस हेतू राजस्थान निरन्तर प्रयासरत है ।

शब्कोशः आत्मनिर्भर, कोविड–19, औद्योगिक विकास, लघु एवं मध्यम उद्योग।

प्रस्तावना

कोरोना संकट से इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है। इस कारण आर्थिक गतिविधियाँ, काम धंधे, उद्योग धंधे पूरी तरह ठप हो गये। ट्रांसपोर्ट चैन भी पूरी तरह बहाल नहीं है । ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और इसके जरिये आत्मनिर्भर बनकर देश को 21वीं सदी का भारत बनाने की बात कही। लोकल उत्पादों को वोकल बनाकर यानी उनका प्रचार कर उन्हें ग्लोबल यानी वैश्विक बनाने का आहवान किया, अर्थात्–स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिये जाने की बात कही ताकि आर्थिक क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन सके ।

इसके लिये उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तम्भों को व्यक्त किया :

- अर्थव्यवस्था–जो वृद्विशील परिवर्तन के स्थान पर बडी उछाल पर आधारति हो।
- अवसरंचना – ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने ।
- प्रौद्यागिकी – 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली।
- गतिशील जन सांख्यिकी – जो आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जाका स्त्रोत है ।
- मांग – भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये ।

सरंक्षणवाद की आशंकाओं को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वकेन्द्रित होना नहीं, बल्कि हमारा लक्ष्य दुनिया में शंति और समृद्धि पैदा करना है।

- **राजस्थान राज्य की स्थिति**

राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बडा राज्य है। किन्तु इसका 61 प्रतिशत भू–भाग मरूस्थलीय है। राज्य में मानसून सबसे अन्त में प्रवेश करता है, साथ ही वर्षा की अनिश्चितता एवं कमी भी अर्थव्यवस्था के मार्ग को अवरूद्ध कर देती है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत, जनसंख्या 5 प्रतिशत एवं बोया गया क्षेत्र 10.6 प्रतिशत है, वहीं जल संसाधनों की उपलब्धता मात्र 1 प्रतिशत है।

* एसिस्टेन्ट प्रोफेसर (व्यवसायिक प्रबन्ध), सोनादेवी सेठिया गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, सुजानगढ़, राजस्थान।

राज्य में सीमित साधनों तथा अकाल व बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए, विकास की अनवरत प्रयास किया है। राज्य की विशेष आवश्यकताओं, अर्थव्यवस्था की क्षमता एवं विकास में आ रही प्रमुख बाधाओं को दृष्टिगत रखने के साथ ही साथ, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह राजसथान ही है, जहाँ देश के जन संख्या के पाँच प्रतिशत भाग को, देश के जल संसाधनों के मात्र एक प्रतिशत से ही कार्य चलाना पडता है।

विगत दशकों में राज्य 12 पंचवर्षीय योजनाओं एवं अनेक वार्षिक योजनाओं को पूरा कर चुका है, राज्य की अर्थव्यवस्था में अनेक रंग उभरे हैं और आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को समाप्त करने की दिशा में मजबूती से प्रयास किये गये हैं। किन्तु यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखे तो अन्य राज्यों से विभिन्न क्षेत्रों में, राजस्थान आज भी पिछड़ा हुआ है। इसके मुख्य कारण राष्ट्रीय औषत की तुलना में प्रति व्यक्ति योजना व्यय में कमी वित्तीय स्त्रोतों की कमी और राष्ट्रीय विनियोजन में राज्य का 2 प्रतिशत से कम हिस्सा है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्तव को स्वीकार करते हुए सरकार ने इन उद्योगों के विकास हेतु विशेष बल दिया। 1948 में घोषित देश की प्रथम औद्योगिक नीति में लघु व कुटीर उद्योगों के महत्तव पर प्रकाश डाला गया। योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास की संस्तुति की। औद्योगिक (विकास और नियमन) अधिनियम, 1951 में देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के आशय से लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया। भारत में लघु उद्योगों के संवर्द्धन और विकास के लिए राज्य के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रिय मंत्रालय के रूप में अक्टूबर, 1999 में लघु उद्योग और कृषि व ग्रामीण मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय को सितम्बर 2001 में दो पृथक मंत्रालयों – लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में विभाजित किया गया। 2 अक्टुबर, 2006 से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED ACT 2006) लागू किया गया। 9 मई, 2007 को लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि व ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को विलय करके 'सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय' बनाया गया। यह मंत्रालय अब सूलम 3 (MSME) क्षेत्र की सहायता व विकास करने हेतू नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने और उनके कार्यान्वयन की मांनिटरिंग करता है।

राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योग यहाँ के लोगों का जिविकोपार्जन का मुख्य साधन है। राजस्थान मु मुख्यतः कृषि, पशु, वनों व खनिज पर आधारित उद्योग हैं।

- **कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग**
  - तेल घानी उद्योग :– तिलहनों पर आधारित यह उद्योग राजस्थान के लगभग 37 हजार परिवारों की आजीविका का साधन है। इस उद्योग की काफी इकाइयां राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर, गंगानगर एवं पाली जिलों में कार्यरत हैं।
  - गुड व खण्डसारी उद्योग :– राजस्थान के गन्ना उत्पादक जिलों में गन्ने के रस से गुड एवं खण्डसारी उत्पादन के लिये लघु एवं कुटीर उद्योगों के रूप यह उद्योग कोटा, बुंदी, श्रीगंगानगर, भीलवाडा, उदयपुर जिलों में प्रमुख है। राज्य के अन्य भागों में यह उद्योग चल रहा है और उसमें लगभग 55 हजार लोग रोजगार में हैं।
  - आटा उद्योग :– गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में आटा उद्योग पनपा है जो मुख्य रूप से जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगानगर, टोंक, बूंदी और भीलवाडा जिलों में पनप रहे हैं।
  - दाल उद्योग :– राजस्थान में कई प्रकार की दलहन उपज होती है। जिसमें उडद, मूंग, चना, मोट और अरहर आदि से लोग दाल बनाते है और उनकी आद्यौगिक इकाइयां बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाडा, चित्तौड, पाली, भरतपुर, टोंक और अलवर जिलों में कार्यरत हैं।
  - चावल उद्योग :– राजस्थान में चावल उत्पादक क्षेत्रों में यह उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योगों के रूप में चलाया जा रहा है। इसके प्रमुख क्षेत्र बांसवाडा, डूंगरपुर, कोटा – बूंदी, गंगानगर, झालावाड, बारां, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर जिलों में हैं।

- हाथ–करघा, खादी ग्रामोद्योग :– खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से राजस्थान के कई स्थानों पर खादी निर्माण, निवाड़, चादर, तौलिया, धोती आदि वस्त्रों का निर्माण होता है । ये उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में संचालित है। गांधी जयंती पर एक माह के लिए खादी पर विशेष छूट की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है।
- बंधाई, छपाई एवं रंगाई उद्योग :– राजस्थान के कई भागों में रंगाई, छपाई एवं बंधाई उद्योग बडी संख्या में पनपे हैं। रंगाई उद्योग मुख्यतः पाली एवं बालोतरा में है। बंधाई का कार्य जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, कुचामन एवं नागौर में है। छपाई का कार्य मुख्यतः जयपुर, जोधपुर, बाडमेर, चित्तौडगढ़ एवं भरतपुर में होता है।
- गोटा – किनारी उद्योग :– राजस्थान के अजमेर, जयपुर तथा खण्डेला में गोटा किनारी उद्योग काफी लम्बे समये से पनप रहा है । वहां औरत और लडके भी इस कार्य में रोजगारत है ।

- **पशुओं के उत्पाद पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग**
  - चर्म उद्योग :– राजस्थान में चमडे से कई प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है । जूतियां, बटुए, बैल्ट, बैग, आसन आदि वस्तुएं जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर आदि कई स्थानों पर बनती है। बीकानेर में ऊंट की खाल से विविध सामान बनाये जाते है। चमड़े से कोट भी बनाये जाते है जो सर्दी को रोकते है।
  - हाथी दांत का कार्य :– जयपुर इसके लिये राजस्थान का विख्यात केन्द्र है। जोधपुर एवं पाली में भी हाथी दांत की चुडियां बनाई जाती है।
  - पशुओं की हड्डी पीसने का उद्योग :– राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या के 22 प्रतिशत है अतः उनकी हड्डियां बहुतायत से मिलती है जिसे पीसकर अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है हड्डी पीसने के कारखाने प्रायः जयपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाडा एवं पलाना में है।
- **वनों पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग**
  - लकड़ी के विविध सामान के उद्योग :– राजस्थान में लकडी के दरवाजे, फर्नीचर तथा खिलौने बनाने का कार्य काफी लोकप्रिय एवं कलात्मक होता है। रोहिडा तथा शीशम की लकडी से ढोल, ढप, तबला, ढोलक तथा अन्य लकडी के वाद्य यंत्र बनाये जाते है। बांस के पंखे, टोकरायाँ तथा चिक तैयार की जाती है। राज्य के प्रत्येक गाँव एवं कस्बों में लकड़ी चीरने की कई आरा मशीनें कार्यरत है। ये राज्य के प्रायः सभी जिलों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के रूप में चलाये जाते है।
  - कागज उद्योग :– द्योसूण्डा में हाथ से कागज बनाने का कार्य होता है। कोटा के स्ट्राबोर्ड का कारखाना लघु उद्योग के रूप में चला रहा है। इसी प्रकार कागज की कुछ छोटी इकाइयां उदयपुर, बांसवाडा, कोटा, अजमेर में स्थापित की जा सकती है।
  - बीड़ी उद्योग :– राजस्थान में तेन्दू पता बहुत मात्रा में मिलने से राज्य के कई स्थानों पर बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र जोधपुर, चितौडगढ, भीलवाडा, टोंक, कोटा और अजमेर जिले है। टोंक में सरकार की मयूर बीडी फैक्टरी प्रमुख है।
  - दियासलाई उद्योग :– राजस्थान के कई भागों में दियासलाई के लिये नरम लकडी मिलती है अतः अजमेर, पाली, फालना और अलवर आदि स्थानों पर दियासलाई के उद्योग को प्रोत्साहन मिला है।
  - कत्था, गोंद एवं लाख उद्योग :– वनों की उपज पर आधारित ये उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्तवपूर्ण योगदान करते हैं। कत्था राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में खैर के पेड़ से तैयार किया जाता है। इसके मुख्य क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड, सवाई माधोपुर, धौलपुर और अलवर है। धोक, बबूल, खैर, कूमटा और कड़ाचा पेड़ों से गोंद उद्योग को बढ़ावा मिला है। जंगलों में पेड़ों से लाख प्राप्त होती है। उस लाख से चूडियां, खिलौने एवं कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती है। यह उद्योग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में काफी तीव्र गति से बढ़ रहा है।

- **खनिज आधारित उद्योग**
  - संगमरमर उद्योग :–राजस्थान के कई भागों में उत्तम कोटि का संगमरमर मिला है उससे कई उद्योग स्थापित हुए है। यह उद्योग मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौडगढ़, उदयपुर, किशनगढ़ और जयपुर में पनपा है। इसकी कटाई, घिसाई और पोलिशिंग करने की कई लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो गई हैं।
  - इमारती पत्थर उद्योगः– राजस्थान के कई भागों में इमारती पत्थर निकलता है। उसकी घिसाई, कटाई एवं पोलिशिंग के लिये भी राजस्थान में कई लघु उद्योग इकाइयां स्थापित हुई है जिनमें कोटा, रामगंज मंडी, चित्तौडगढ़, उदयपुर आदि प्रमुख हैं।
  - ग्रेनाइट उद्योग :– राजस्थान में अच्छी किस्म का ग्रेनाइट कई रंगों में पाया जाता है। उसकी कटाई, घिसाई एवं पोलिशिंग के कारखाने जालौर, चित्तौड़, उदयपुर तथा जोधपुर में हैं।
- **राजस्थान में अन्य लद्यु उद्योग**

राजस्थान में उपरोक्त उद्योगों के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण लघु उद्योग भी है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

  - ऊन उद्योग :– राजस्थान में लगभग 1.43 करोड भेडों से प्रतिवर्ष 19.5 हजार टन ऊन प्राप्त होती है। उसका उपयोग करने के लिये बीकानेर और जोधपुर में दो कारखाने स्थापित किये गये है। ऊन प्रोसिस करने के लिये 29 फैक्ट्रियां बीकानेर, जोधपुर, ओलिया, सीकर, भीलवाड़ा, केकड़ी, पाली और ब्यावर में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त लाडनूं, चुरू और भीलवाड़ा में वर्स्टेड स्पिनिंग ऊनी मिलें हैं।
  - रसायन उद्योग :– डीडवाना में सोडियम सल्फेट कारखाना, देवारी में रासायनिक खाद बनाने का कारखाना है।
  - इन्जीनियरिंग उद्योग :– राजस्थान में इसके 20 उद्योग है, जयपुर में मीटर बनाने का जयपुर मेटल का कारखाना, बाल बेयरिंग बनाने का कारखाना, पानी के मीटर बनाने का कारखाना आदि उल्लेखनीय हैं। कृषि उपकरणों के लिये सिरोही, चित्तौडगढ़, नागौर, सोजत और दिगोद में कारखाने लगाये गये हैं।

राजस्थान की अनेक कलात्मक वस्तुएँ विश्व भर में लोकप्रिय है। राजस्थान प्राचीनकाल से हस्तशिल्प के क्षेत्र में विश्वविख्यात रहा है। यहां की हस्तशिल्प की कलात्मक कृतियां अब देश – विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों एवं मेलों में भेजी जाती हैं और उनकी मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है, उससे हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिला है। हस्तकलाओं से अभिप्राय हाथ से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं एवं कलाकृतियों से है जो हस्तशिल्पियों अथवा कारीगारों द्वारा तैयार की जाती है। इसके अन्तर्गत हम सोने – चांदी के कलात्मक आभूषणों, पीतल पर खुदाई एवं मीनाकारी के बर्तन, लाख से बनी चूडियां एवं अन्य सजावटी सामान, संगमरमर की सुंदर एवं कलात्मक मूर्तियां, सांगानेरी एवं बगरू प्रिंट के कलात्मक परिधान, हाथी दांत तथा लकडी पर खुदाई के कलात्मक सामान सलमा सितारों की जूतियां आदि सब प्रकार का कलात्मक सामान आता है ।

- **राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएँ**
  - खुदाई एपं मीनाकारी तथा मूल्यवान रत्नों को तराशना :– यह जयपुर में प्रमुख रूप से विकसित हुआ है किन्तु प्रतापगढ़ और नाथद्वारा में भी मीनाकारी का कार्य किया जाने लगा है। जयपुर में मूल्यवान रत्नों को तराशने का कार्य भी प्रसिद्ध है।
  - हाथी दांत की वस्तुएँ :– राजस्थानी महिलाओं में सौभाग्य की प्रतीक हाथी दांत की चूडियां व अन्य सामान जोधपुर में बनाया जाता है। जयपुर में हाथी दांत के खिलौने, कलात्मक वस्तएँ तथा सजावटी सामना तैयार होता है। इसके अतिरिक्त उदयपुर, पाली एवं भरतपुर में हाथी दांत का सामान बनने लगा है।

- संगमरमर की मूर्तियाँ एवं कलात्मक सामान :– मुख्तः जयपुर में केंद्रित है। इसके अतिरिक्त अलवर एवं किशनगढ़ जिले के किशोर ग्राम में भी यह सामान बनाया जाता है।
- लाख एवं कांच की चुडियाँ एवं कलात्मक सामान :– जयपुर एवं जोधपुर में विविध रंगों की चूडियाँ एवं कलात्मक सामान लाख एवं कांच से बनाया जाता है। जिनमें खिलौने, मूर्तियां, गुलदस्ते, हार अंगूठियां, कर्णफूल, झुमके तथा चाबियों के गुच्छे आदि का निर्माण मुख्य है।
- कशीदाकारी :– वस्त्रों पर कलात्मक और कुशलतापूर्वक कशीदाकारी का कार्य जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बाड़मेर में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है ।
- रंगाई, छपाई और बन्धेज के वस्त्र :– इस कार्य में राजस्थान की दूर – दूर तक ख्याति है। पाली, बाडमेर और सांगानेर में रंगाई, छपाई और बंधेज का कार्य बडी मात्रा में होता है। चित्तौड़ में जाजम छपाई, बाड़मेर का अजरक प्रिंट तथा सांगानेरी छपाई के लिये जयपुर का सांगानेर प्रसिद्ध है।
- ऊनी कम्बल, गलीचे एवं कालीन :– इनको बनाने में जोधपुर, बीकानेर, बाडमेर, मालपुरा और टोंक प्रसिद्ध है। राजस्थान के गलीचे, नमदे और कालीन विदेशों में निर्यात किये जाते हैं ।
- चमड़े पर हस्तशिल्प :– चमड़े का कलात्मक सामान राजस्थान की प्रमुख विशेषता है । यहां की कलात्मक मौजडियां, जूतियां, पर्स, बैग बेल्ट, आसन तथा बीकानेर में ऊंट की खाल से बनाये जाने वाले सजावटी सामान प्रमुख है। ये मुख्य रूप से जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बाडमेर आदि स्थलों पर बनाये जाते हैं।
- लकड़ी पर नक्काशी का काम एवं खिलौने एवं सजावट का सामान :– इसक निर्माण उदयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर तथा बाड़मेर और चित्तौड़ के बस्सी गांव में बनाये जाते है। बस्सी गांव लकडी के शेर, हाथी, घोड़े, फड़ एवं गणगौर बनाने की दृश्टि से प्रसिद्ध है।

राजस्थान में औद्योगिक विकास की वृहद् सम्भावनाएँ है। इस क्षेत्र में राज्य निरन्तर प्रगति कर रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से आज तक केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के प्रभावी प्रयास किये गये है। भारत एवं राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतू वित्तीय एवं औद्योगिक तंत्र की अनेक सार्वजनिक इकाइयां की स्थापना की गई।

इस हेतू भारतीय सार्वजनिक वित्तीय स्ंस्थाओं द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की निम्न इकाइयों ने राज्य के औद्योगिक विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान दिया है ।

- भारतीय औद्योगिक निगम 1948
- भारतीय औद्योगिक साख एवं विनयोग निगम 1955
- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964
- भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक 1971
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 1982
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लिमिटेड 1989
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1955

साथ ही भारत सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए निम्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किये गये –

- हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर 1965
- हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी 1967
- हिन्दुस्तान मशीन टूल्स निगम, अजमेर 1967
- इन्स्टूमेंटेंशन लिमिटेड, कोटा
- साभंर साल्ट्स लिमिटेड, सांभर 1964

राजस्थान में अनेक औद्योगिक घराने होने के बाद भी प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। बिडला, डालमिया, सिंघानिया पोददार, बजाज आदि अनेक विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने – राजस्थान में जन्म लेकर आगे बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से बीमारू राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास के लिए निम्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना की गई –

- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड (रीको) 1969
- राजस्थान वित्त निगम 1955
- सार्वजनिक उपक्रम बयूरो
- उद्योग विदेशालय
- जिला उद्योग केंद्र
- राजस्थान लघु उद्योग निगम 1961

राजस्थान सरकार ने भी औद्योगीकरण हेतू स्वयं साहसी के रूप में लेख उपक्रम स्थापित किये है –

- हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर
- गंगानगर शुगर मिल्स
- राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, ड़ीडवाना
- साल्ट वर्क्स ड़ीडवाना एवं पंचभद्रा
- टोंक में चमडा बनाने की कारखाना
- स्टेट वूलन मिल्स, बीकानेर
- वास्टेड वूलन मिल्स, लाडंनू एवं चुरु

राजस्थान अपने औद्योगिक विकास हेतू निरन्तर कार्यरत है जिसमें उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के संर्वद्धनात्मक कार्य भी किये जा रहे हैं, किन्तु इस वैश्विक महामारी ने ना केवल राज्य की बल्कि सम्पूर्ण देश या कहे सर्म्पूण विश्व की औद्योगिक विकास की गति को काफी धीमा कर दिया है । इस हेतू प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है । यह पैकेज कोविड–19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई पूर्व सरकारी घोषणाओं तथा त्ठप् द्वारा लिये गये निर्णयों को मिलाकर 20 लाख करोड रूपये का है, जो भारत की ''सकल घरेलू उत्पाद'' ;ळक्च्द्ध के लगभग 10ः के बराबर है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की स्थापना के माध्यम से दो मुख्य लक्ष्यों (औद्योगिक विकास और रोजगार) को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। वर्तमान में कोविड–19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों में अधिकांश कंपिनयों में ऑटोमेशन, घर से काम करने और अनुबंधित कामगारों को अधिक प्राथमिकता दे रही है । औद्योगिक विकास के साथ – साथ ही उत्पादन के स्वरूप और कम्पनीयों और उद्योगों की कार्यशैली में बड़े बदलाव किये जा रहे हैं। ऐसे में कृषि और अन्य क्षेत्रों को इन परिवर्तनों के अनुरूप तैयार कर औद्योगिक विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा सकता है। उदाहरण के लिये विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों की पैकेजिंग या उनसे बनने वाले अन्य उत्पादों के निर्माण हेतू स्थानीय स्तर पर छोटी औद्योगिक उत्पादन श्रृखंला में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है ।

राजस्थान अपने लघु, कुटीर व हस्तशिलप, हथकरद्या और खादी उद्योगों के लिये विश्वविख्यात है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान से जयपुर के निकट बगरकटवुर्द गाँव की ग्रामीण महिलाओं ने जुड़कर यह साबित कर दिया है वे अपने परिवार को आर्थिक संबल दे सकती है। इन महिलाओं ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि कोरोना काल में परिवार के सदस्यों की नौकरियाँ चली गई तो आगे बढ़कर परिवार को भी संभाला। राजस्थान के गाँवों में महिलाओं ने कोरोना काल में न सिर्फ अपने कौशल में वृद्धि की बल्कि कमाई कर परिवार को आर्थिक संबल भी दिया। ये महिलाएँ स्वयं सहायता से जुडकर पैसे कमा रही है, कोई गोबर के दीपक बना रही है तो कोई ब्लयू पॉटरी, कोई हैडीक्राफ्ट के जरिए हस्तकला क्षेत्र में अपनी धाक जमा रही है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है।

केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मध्यम, सूक्षम और लघु उद्योगों के लिये घोषित पैकेज का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बारे में सुझाव देने के लिये राज्य सरकार ने अपना कार्य किया है। राजस्थान में मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग बडी संख्या में है। इसके अलावा हस्तशिल्प बुनकर और खादी की भी काफी इकाइयां राजस्थान में काम कर रही है। राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पाद पूरी दुनिया में निर्यात किये जाते है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस प्रकार के उद्योगों के लिये करीब 73 हजार करोड का पैकेज घोषित किया है। अपने शांत औद्योगिक वातावरण व उपलब्ध औद्योगिक भूखण्ड के कारण राजस्थान औद्यागिक निवेश के लिहाज से भारत का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा है। औद्योगिक विकास नीति 2019 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 सौर ऊर्जा नीति 2019 और पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 आदि ने निवेशकों के लिए मरूधारा के दरवाजे खोल दिये है। एमएमएसई ;डडैम्द्ध को लेकर बनाई गई नीतियों ने भी प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को संवारने का काम किया। राजस्थान औद्योगिक निवेश संभावनाओं पर काम कर रहा है, यह तब हो रहा है जब कोविड–19 के चलते नए काम धंधा के सफल संचालन की सम्भावनाएँ कम है। आपदा के बीच में राजस्थान पहला वह राज्य जिसने एक साथ 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों को लान्च किया है। कोविड – 19 ने लोगों के जीने का तरीका बदल दिया है। हर क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। उद्योगों, धंधों की रफ्तार पर लगा ब्रेक अनलॉक फेज प्रभावी होने से खुलने लगा है। ऐसे में राजस्थान के उद्योग विभाग ने अपनी नीतियों में अंहम् बदलाव किए है जिनका मकसद यही है कि राजस्थान में नया औद्योगिक निवेश आए, जिससे रोजगार और राजस्व के आंकडें सुखद स्थिति में हो और एक नये भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लक्ष्मी नारायण नाथूरामका, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कॉलेज बुक हाऊस, 2013, जयपुर ।
2. प्रकाश नारायण नाटाणी, अपना राजस्थान, पिंक सिटी पब्लिशर्स, 1995, जयपुर ।
3. कान्तिजैन, महावीरजैन, राजस्थान का भूगोल व अर्थव्यवस्था, मनु प्रकाशन प्रो. लिमिटेड – 2018, जयपुर।
4. आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार, 2012–13, जयपुर
5. वार्षिक प्रतिवेदन, राजसिको, उद्योग भवन, राजस्थान सरकार 2003, जयपुर ।
6. प्रकाशित प्रपत्र, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
7. न्यूजडिटेल, राजस्थान सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ।
8. www.patrika.com
9. epaper.livehindustan.com

❖◆❖